दिल्ली राउंड टेबल ऑन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट (DRT)

दिल्ली, भारत में **COVID-19** संकट और असंगठित क्षेत्र: चालू आर्थिक प्रभाव और असमान रिकवरी

तस्वीर: रश्मि चौधरी द्वारा WEIGO के लिए

मुख्य निष्कर्ष

- असंगठित कामगारों के लिए कोई रिकवरी नहीं: महामारी और संबंधित सरकारी उपायों से 2021 में असंगठित कामगारों की आजीविका पर नकारात्मक प्रभाव कम होने और उलटने के बजाय जारी है और गहरा हो रहा है. औसत काम के दिनों को देखें तो कचरा कामगार, घरेलू कामगारों, घर-खाता कामगारों और फुटपाथ विक्रेताओं के लिए रिकवरी असमान और बिखरी हुई रही है. कामगारों की कमाई सभी क्षेत्रों में पूर्व-कोविड-19 स्तर से नीचे बनी हुई है.

- घर-खाता कामगार सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र: चारों क्षेत्रों में संकट के असर की कहानी अलग-अलग है. घर-खाता कामगार (जो कोविड-19 से पहले भी सबसे कम कमाई का क्षेत्र था)

अभी भी सबसे बुरी तरह प्रभावित हैं. मध्य-2021 में घर-खाता कामगारों के लिए मीडियन आय अभी भी शून्य है, अन्य क्षेत्रों के विपरीत जहां कमाई में कुछ रिकवरी हुई है.

- महिला कामगारों पर असमानुपातिक रूप से नकारात्मक प्रभाव: जिन क्षेत्रों में विशेष रूप से महिला कामगार ज़्यादा हैं - घर-खाता कामगार और घरेलू कामगार - उनकी स्थिति ज्यादा बदतर है. अध्ययन में लिए गए बाकी क्षेत्रों से महिला कामगार वाले क्षेत्रों में अधिक बेरोजगारी, आय में अधिक गिरावट और काम के दिनों की संख्या में कमी देखी गई है. यहां तक कि मिश्रित-लिंग वाले क्षेत्रों - कचरा बीनने वाले और फुटपाथ विक्रेता - में महामारी ने पुरुषों और महिलाओं की कमाई के बीच मौजूदा अंतर को मध्य-2021 तक तीन गुना बढ़ा दिया, जिससे महिलाओं की कमाई और भी पीछे रह गई है.

- आय गिर रही है जबकि कर्ज बढ़ रहा है: घरेलू स्तर पर आर्थिक तनाव काफी ज्यादा है: 70% कामगारों ने घरेलू आय स्तर में नुकसान दर्ज कराया; 90% कामगार जिन्होंने महामारी से निपटने के लिए बचत का सहारा लिया, उनके पास उसकी भरपाई का कोई जरिया नहीं है; 70% कामगारों ने दर्ज किया कि उन्हें महामारी से निपटने के लिए काफी ज्यादा मात्रा में कर्ज उठाना पड़ा

- कामगार भोजन असुरक्षा का अनुभव कर रहे हैं: मध्य-2021 में भी कई उत्तरदाताओं ने बताया कि पिछले महीने उनके घर में वयस्क और बच्चे भूखे थे. लगभग आधे (44%) लोगों ने भोजन सुरक्षा की बात की और बताया कि उनके परिवार को कई वक्त का भोजन छोड़ना पड़ा या भोजन की मात्रा कम करनी पड़ी. ये सब इसके बावजूद है कि अधिकांश कामगारों को भोजन के लिए सरकार और MBO से मदद मिली.

- संकट का सामना करने के लिए सरकारी मदद अपर्याप्त है: संकट के दौरान सरकार या औपचारिक संस्थानों से बहुत कम या कोई समर्थन नहीं मिला. संकट का सामना करने के लिए कामगारों को अपनी स्वयं की बचत और सामाजिक नेटवर्क पर निर्भर रहना पड़ा. ये बिंदु और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इन कामगारों में से अधिकांश प्रवासी हैं.

- देखभाल की जिम्मेदारियां बढ़ी हैं: देखभाल का बोझ अभी भी काफी ज्यादा है. इससे काम करने की क्षमता और भुगतान योग्य काम पर खर्च किए गए समय, दोनों पर असर पड़ा है. देखभाल की जिम्मेदारियों का बोझ महिलाओं पर असमान रूप से पड़ा है, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें भुगतान योग्य काम का नुकसान सहना पड़ा है.

सिफारिशें

- मान्यता और विनियमन: सरकार को असंगठित कामगारों को मान्यता देनी चाहिए और उन्हें श्रम कानूनों के दायरे में लाकर न्यूनतम आय की गारंटी देनी चाहिए. उचित वेतन तथा कामगारों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए असंगठित कामगारों के नियोक्ताओं को सख्त दिशा-निर्देश जारी किए जाने चाहिए. राज्य को सभी को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए सक्रिय उपाय करने चाहिए, जैसे कि बच्चों की देखभाल, स्वास्थ्य देखभाल और पेंशन, साथ ही इन सुविधाओं तक पहुंचने वाली बाधाओं को हटाने के उपाय करने चाहिए.

- आजीविका के अवसर प्रदान करें: राज्य को रोजगार सृजन के लिए सक्रिय आर्थिक उपायों द्वारा आजीविका को पुनर्जीवित करने के लिए ठोस कार्रवाई करनी चाहिए. साथ ही पूंजी की उपलब्धता

को बढ़ावा देने के लिए नकद अनुदान का प्रावधान करना चाहिए. अंतरिम तौर पर, कामगारों की आय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रत्यक्ष नकद अनुदान की व्यवस्था की जानी चाहिए. राज्य के लिए जरूरी है कि वो नकारात्मक उपायों को वापस ले. जैसे, रेहड़ी-पटरी बाजारों को बंद करना और निजी क्षेत्र द्वारा कूड़े के निस्तारण के लिए अनुचित मशीनीकरण.

- कोई नुकसान न करें: कानून प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक स्थान पर काम करने वाले असंगठित कामगारों को बेदखल और परेशान नहीं करना चाहिए. निजी निवासी कल्याण निकायों (रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (RWA)) के अनुचित नियम, जो घरेलू कामगारों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं, उन्हें स्थानीय अधिकारियों द्वारा रोका जाना चाहिए.
- हमारे बिना, हमारे लिए कुछ भी नहीं: असंगठित कार्यकर्ताओं और उनके संगठनों को ऐसे नीतिगत मंच के साथ प्रमुख हितधारकों के रूप में जोड़ा जाना चाहिए, जिनके बनाए नियमों से उनके काम पर असर पड़ता है.
- रहने और काम करने के लिए गुणवत्तापूर्ण और सुरक्षित स्थितियां सुनिश्चित करें: सरकार को गुणवत्तापूर्ण आवास के अधिकार को मान्यता देनी चाहिए और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक एक तत्काल उपाय के रूप में बुनियादी सेवाओं के सार्वभौमिक प्रावधान को सुनिश्चित करना चाहिए. महामारी जब तक खत्म नहीं हो जाती तब तक सब्सिडी युक्त भोजन राहत (राशन कार्ड और प्रवास की स्थिति से इतर) और सामुदायिक रसोई के माध्यम से पोषण सहायता सुनिश्चित की जानी चाहिए.

पृष्ठभूमि

कोविड**-19** संकट और असंगठित अर्थव्यवस्था, WIEGO के नेतृत्व में की गई एक लोंगिट्यूडनल स्टडी है जो असंगठित कामगारों और उनके परिवारों के विशिष्ट समूहों पर COVID-19 संकट के प्रभाव का आकलन करती है.[1] सर्वेक्षण प्रश्नावली और गहन साक्षात्कार का उपयोग करते हुए, पहले राउंड में फरवरी 2020 (पूर्व-कोविड-19 अवधि) की तुलना में अप्रैल 2020 और मध्य-2020 में संकट के प्रभाव का आकलन किया गया था.[2] दूसरा राउंड 2021 के मध्य में आयोजित किया गया था ताकि यह आकलन किया जा सके कि कामगार कैसे COVID-19 संकट दोबारा सक्रिय होने और चालू आर्थिक तनाव का अनुभव कर रहे थे, और वे किस हद तक (यदि कोई) रिकवर कर पाए. यह रिपोर्ट दिल्ली, भारत में किए गए अध्ययन के दूसरे राउंड का सारांश निष्कर्ष प्रस्तुत करती है. दिल्ली में शोधकर्ताओं ने पहले राउंड के 265 मूल उत्तरदाताओं में से 204 का सर्वेक्षण किया ताकि यह आकलन किया जा सके कि प्रारंभिक सर्वेक्षण के लगभग एक साल बाद उनकी स्थिति कितनी बदली. 5 अन्य उत्तरदाताओं का सर्वेक्षण किया गया. शोधकर्ताओं ने 4 असंगठित कामगारों और 4 असंगठित कामगार नेताओं के साथ गहन साक्षात्कार भी किए. यह शोध सेवा, जनपहल और 'दिल्ली राउंडटेबल ऑन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट' के सहयोग से किया गया.

दिल्ली में असंगठित अर्थव्यवस्था[3]

---

[1]अध्ययन के शहर हैं अकरा (घाना), अहमदाबाद (भारत), बैंकॉक (थाईलैंड), डकार (सेनेगल), दार एस सलाम (तंजानिया), दिल्ली (भारत), डरबन (दक्षिण अफ्रीका), लीमा (पेरू), मैक्सिको सिटी (मेक्सिको)), न्यूयॉर्क शहर (यूएसए), प्लेवेन (बुल्गारिया), तिरुपुर (भारत).

[2]दिल्ली में राउंड 1 के परिणाम यहां उपलब्ध हैं:
https://www.wiego.org/publications/covid-19-crisis-and-informal-economy-informal-workers-delhi-india

[3] इस खंड में आंकड़े रवींद्रन, जी और वानेक, जोएन से लिए गए हैं. 2020 'असंगठित कार्यकर्ता भारत में: एक सांख्यिकीय प्रोफ़ाइल'; सांख्यिकीय संक्षिप्त संख्या 24, WIEGO प्रकाशन श्रृंखला. यहां उपलब्ध है:
https://www.wiego.org/publications/informal-workers-india-statistical-profile

दिल्ली में अधिकांश कामगार असंगठित रूप से काम करते हैं. नवीनतम अनुमानों के अनुसार दिल्ली में क़रीब 49.2 लाख असंगठित कामगार हैं. ये संख्या कुल कार्यबल के 80% से अधिक है. महिलाएं कुल कार्यबल का लगभग 15% हिस्सा है, लेकिन इनमें से 76.4% महिलाएं असंगठित अर्थव्यवस्था में काम करती हैं. घर खाता कामगार, घरेलू कामगार, फुटपाथ विक्रेता और कचरा कामगार, ये सब मिलकर दिल्ली के कुल कामगारों का 14% और असंगठित क्षेत्र के कामगारों का 17% हिस्सा हैं. असंगठित महिला कामगारों के लिए ये चार क्षेत्र, कुल रोजगार का लगभग 22% और असंगठित क्षेत्र के रोजगार का लगभग 30% हिस्सा हैं. सभी चार क्षेत्रों में अधिकांश कामगार, दैनिक रूप से बहुत लम्बा श्रम करते हैं. उन्हें बहुत कम भुगतान मिलता है और उनकी कमाई अक्सर न्यूनतम वेतन मानकों से भी कम होती है. सभी कामगार समूहों में, पुरुषों की तुलना में महिलाएं कम कमाती हैं.

दिल्ली में **COVID-19:** मुख्य तिथियां

25 मार्च**, 2020** : केवल आवश्यक सेवाओं को छोड़कर, 14 अप्रैल तक राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की गई. अगले ही दिन से दिल्ली और अन्य प्रमुख भारतीय शहरों से प्रवासी पलायन शुरू हो गया. लॉकडाउन को तीन बार बढ़ाया गया और मई 2020 के अंत तक चला.

8 जून**, 2020:** अनलॉक दिशानिर्देशों के क्रमिक संशोधन के साथ चरणबद्ध रूप से दोबारा खुलने की प्रक्रिया शुरू हुई.

16 जनवरी**, 2021:** स्वास्थ्य कर्मियों के लिए टीकाकरण कार्यक्रम शुरू

1 मार्च**, 2021:** वरिष्ठ नागरिकों और 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों (जिन्हें साथ में कोई कोमॉर्बिडिटी हो) के लिए टीकाकरण अभियान शुरू हुआ.

मध्य-मार्च- मई**, 2021:** डेल्टा संस्करण की आमद के साथ कोविड-19 मामले बढ़े, जिसके परिणामस्वरूप मृतकों की संख्या में गंभीर इज़ाफ़ा हुआ और बुनियादी स्वास्थ्य ढांचा चरमरा गया. दिल्ली भारत के सबसे बुरी तरह प्रभावित शहरों में से एक था, जहां संकट के चरम पर प्रतिदिन 25,000 से अधिक मामले और 400 से अधिक मौतें दर्ज की गई.

1 अप्रैल**:** 45 वर्ष से ऊपर की आयु के सभी नागरिकों के लिए टीकाकरण अभियान शुरू

19 अप्रैल**:** दिल्ली में 31 मई तक लॉकडाउन लगा दिया गया.

1 मई**, 2021:** सभी वयस्कों (18+) के लिए टीकाकरण शुरू किया गया

1 जून**, 2021:** दूसरी लहर के बाद दोबारा खुलने की प्रक्रिया शुरू हुई.

अध्ययन तिथियां और सैंपल

दिल्ली में अध्ययन की तिथियां

- राउंड **1:** जून- जुलाई 2020
- राउंड **2:** सितंबर- अक्टूबर 2021[4]

[4] अध्ययन का दूसरा दौर, जिसे पहले जून 2021 में प्लान किया गया था, उसे शहर में कोविड -19 की दूसरी लहर (जो अप्रैल 2021 में शुरू हुई) के कारण तीन महीने पीछे धकेलना पड़ा.

टोटल सैंपल: सर्वे के दोनों राउंड में, सैंपल में चारों सेक्टर शामिल थे. राउंड 2 के लिए सैंपल साइज 209 था.[5]
सेक्टर और नए बनाम **R1** उत्तरदाताओं के हिसाब से सैम्पल[6]

क्षेत्र	संख्या	कुल सैंपल का %	% महिलाएं	% नए उत्तरदाता
घरेलू कामगार	46	22	100	0
घर-खाता कामगार	54	26	100	0
फुटपाथ विक्रेता	61	29	38	8
कचरा कामगार	43	21	27	0
अन्य	5	2	60	0
कुल	209	100%	66%	2%

आयु संवितरण

	संख्या	%
18-25	20	10
26-35	60	29
36-45	70	34
46-55	41	20
56-65	10	5
> 65	2	1

सैम्पल प्रत्येक शहर में असंगठित कामगारों या प्रत्येक भागीदार संगठन की सदस्यता के प्रतिनिधित्व का दावा नहीं करता.

[5]राउंड 1 के 61 उत्तरदाताओं का राउंड 2 में सर्वेक्षण नहीं किया गया. इसका सबसे आम कारण कामगारों तक पहुंचने में असमर्थता थी क्योंकि उनके फोन नंबर अब मान्य या उपलब्ध नहीं थे. फिर भी, शोधकर्ताओं ने कामगारों से संपर्क करने के लिए निरंतर प्रयास किए - भौतिक रूप से कामगारों के अंतिम ज्ञात घरों और कार्यस्थलों का दौरा किया. इस प्रक्रिया में, यह पाया गया कि कई कामगार दूर चले गए थे और उनका पता लगाने का कोई तरीका नहीं था. एक मामले में, टीम को एक रेहड़ी-पटरी वाले उत्तरदाता की कोविड-19 के कारण मौत के बारे में भी पता चला. "शोध थकान" को एट्रिशन के लिए एक अतिरिक्त कारण के रूप में उद्धृत किया गया.
[6]R1 उत्तरदाता जिन्होंने अपना प्राथमिक व्यवसाय बदल लिया है, उन्हें "अन्य" के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जब तक कि वे अन्य मुख्य क्षेत्रों (स्ट्रीट वेंडिंग, कचरा उठाने, घर-खाता काम या घरेलू काम) में से एक नहीं बन जाते हैं, इस मामले में उन्हें इसके सदस्य के रूप में शामिल किया जाता है. समूह. R1 उत्तरदाताओं, जिन्होंने पूरी तरह से काम करना बंद कर दिया है या सर्वेक्षण के समय काम नहीं कर रहे थे, उनके R1 सेक्टर के साथ सारणीबद्ध हैं.

संकट के प्रभाव और प्रतिक्रिया

काम, कमाई और भोजन

जब मार्च 2020 में दुनिया पर कोविड -19 महामारी की मार पड़ी, तो सरकारों ने इस बीमारी फैलने से रोकने के लिए तुरंत प्रतिक्रिया करते हुए सख्त उपाय लागू किए. भारत में इन उपायों से आशय था, सख्त लॉकडाउन और घर पर रहने के आदेश, जिनका असंगठित कामगारों की आजीविका पर तत्काल प्रभाव पड़ा और महामारी ने उन्हें कमजोर कर दिया.

अब जबकि महामारी को डेढ़ साल से ज्यादा का वक्त हो गया है, कोविड की दूसरी कठोर लहर के बाद, दिल्ली में असंगठित कामगार अभी भी अपने काम और कमाई को लगे गंभीर झटके से जूझ रहे हैं, और रिकवरी भी धीमी और असमान है. दिल्ली में असंगठित कामगारों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति कोविड-पूर्व काल के आसपास भी नहीं है.

काम

मध्य-2021 में, यह पूछे जाने पर कि क्या वे पिछले महीने में एक दिन भी काम कर पाए, एक चौथाई (28%) से अधिक कामगारों ने 'नहीं' में जवाब दिया. अगर काम करने की क्षमता को आजीविका की रिकवरी का संकेत माना जाए, तो हम देखते हैं कि 2020 के बाद से थोड़ा सुधार हुआ है. मार्च से जून, 2020 तक कठोर लॉकडाउन के कारण काम का नुकसान हुआ. जिसके चलते अधिकांश कामगार (80%) अप्रैल 2020 में एक भी दिन काम नहीं कर पाए. प्रतिबंधों में ढील के साथ मध्य-2020 तक लगभग 50% कामगार दोबारा काम शुरू करने में सक्षम हुए. हालांकि एक साल बाद भी रिकवरी समान या पूर्ण नहीं है. पुरुषों की तुलना में महिला कामगारों के लिए दोबारा काम शुरू करना अधिक कठिन रहा है. मध्य-2021 में केवल 7% पुरुष एक दिन भी काम नहीं कर पाए, वहीं महिलाओं में ये संख्या 39% थी. इस आंकड़े को क्षेत्रवार परिणामों के संदर्भ में समझना होगा- घरेलू कामगार और घर-खाता कामगार जैसे महिला-प्रधान क्षेत्रों में काम दोबारा शुरू करने में सबसे ज्यादा कठिनाई हुई. 52% घर-खाता कामगार और 37% घरेलू कामगार मध्य-2021 में एक दिन भी काम नहीं कर पाए.

जो काम कर पा रहे हैं, उनके लिए चारों क्षेत्रों में, प्रति सप्ताह कार्य दिवसों की औसत संख्या गिर गई है- महामारी से पहले 6 दिन प्रति सप्ताह काम कर रहे थे, मध्य-2021 में सिर्फ 4 दिन प्रति सप्ताह काम कर पा रहे हैं. घरेलू काम और घर-खाता काम जैसे महिला प्रधान क्षेत्रों में प्रति सप्ताह काम करने के दिनों की औसत संख्या कोविड-19-पूर्व की तुलना में आधी हो गई है.

काम की स्थिरता भी सतत नहीं है. पिछले 12 महीनों में, दिल्ली में कोविड-19 संक्रमण के फैलने की दर बदलती रही है, जिसके चलते कामगारों के ऊपर लागू नियम भी लगातार प्रभावित हुए हैं. मध्य-2020 से, 49% उत्तरदाताओं ने बताया कि कम से कम एक महीना अवश्य ऐसा रहा जब वो 10 या 10 से ज़्यादा ज़्यादा दिनों तक काम नहीं कर पाए. 28% उत्तरदाताओं के लिए, यह कम से कम 3 महीने या उससे अधिक था.

इसके अतिरिक्त, घरेलू काम और घर-खाता काम जैसे महिला-प्रधान क्षेत्रों में लगातार ऊंची संख्या में उत्तरदाताओं ने बताया कि जब बीमारी कम थी और प्रतिबंधों में अपेक्षाकृत ढील दी गई थी, उन महीनों में

भी वो काम नहीं कर पाए. इसके इतर फुटपाथ विक्रय और कचरा उठाने जैसे क्षेत्रों में, अधिकांश ने बताया कि सिर्फ़ अप्रैल-मई 2021 वह अवधि थी, जब वे काम करने में असमर्थ थे. इस अवधि के दौरान दिल्ली में दूसरी लहर अपने चरम पर थी, जब लॉकडाउन दोबारा लागू किए गए और सार्वजनिक स्थान बंद कर दिए गए.

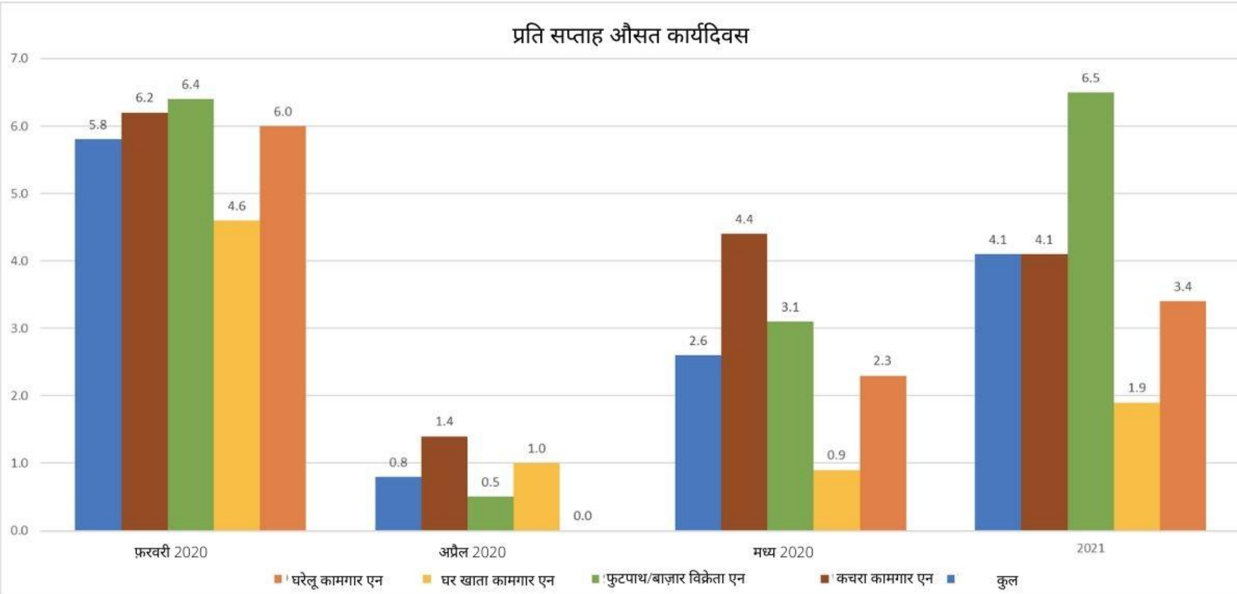

नोट: उत्तरदाताओं को पिछले सात दिनों में कार्य दिवसों को रिपोर्ट करने के लिए कहा गया था. इसमें वे दिन भी शामिल हैं, जिनके दौरान उन्होंने अंशकालिक काम किया था.

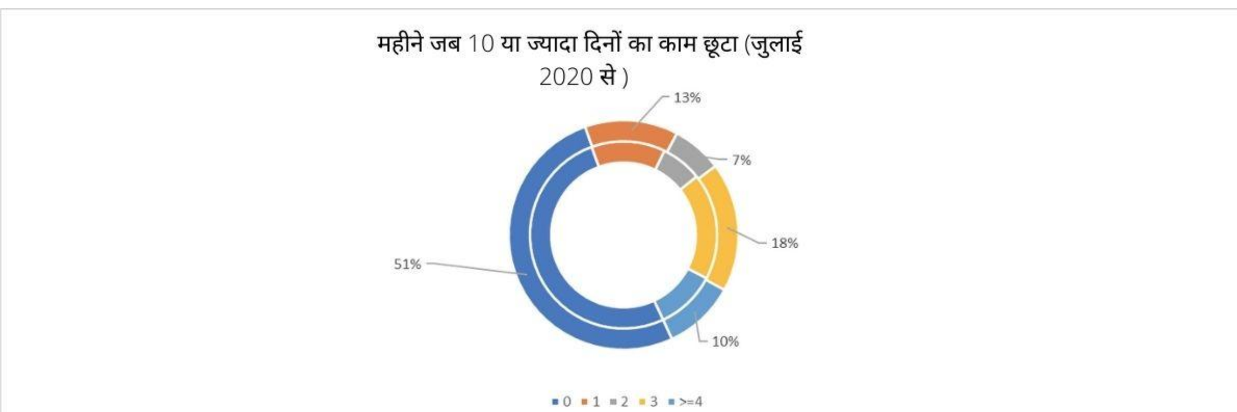

काम और कमाई के लिए कामगारों द्वारा बताई गई मुख्य बाधाएं थीं: प्रतिबंध, जिनमें सरकारी प्रतिबंध शामिल हैं, बाजार बंद होना और काम के लिए अनुमति हासिल न कर पाना (66%), बाजार और आपूर्ति श्रृंखला के मुद्दे जिनमें ग्राहकों की मांग में कमी शामिल है, कार्य आदेशों (वर्क ऑर्डर) की कमी और काम से निकाला जाना (32%), और बीमारी और बीमारी के डर सहित स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं (18%). सभी क्षेत्रों में, सरकारी प्रतिबंधों को काम करने में प्रमुख बाधा के रूप में उद्धृत किया गया, जो दिल्ली में लॉकडाउन के व्यापक प्रभाव को दर्शाता है, यहां तक कि उन कामगारों पर भी जो सार्वजनिक स्थान पर काम नहीं करते. सरकारी प्रतिबंधों (बाजार बंद होने) से फुटपाथ विक्रेता सबसे अधिक प्रभावित हुए. ये प्रतिबंध दिल्ली शहर के अधिकतर इलाकों में 2020 के अंत तक लागू थे, और अप्रैल से अगस्त 2021

तक जब कोविड के मामलों में बढ़ोतरी हुई, दोबारा लागू हुए . छँटाई केंद्र बंद करने के रूप में प्रतिबंधों से कचरा कामगार सबसे अधिक प्रभावित हुए. घरेलू कामगारों और घर-खाता कामगारों के लिए बाजार और आपूर्ति श्रृंखला के मुद्दे काम और कमाई के लिए दूसरी सबसे आम बाधा थे. घरेलू कामगारों के लिए इसने काम के नुकसान (नियोक्ताओं द्वारा कामगारों को काम से निकालना) और नए काम के अवसर की कमी (नियोक्ताओं द्वारा लोगों का काम पर न रखना) का रूप लिया. घर-खाता कामगारों के लिए बाजार या आपूर्ति-श्रृंखला संबंधी सबसे आम बाधा थी, कार्य आदेशों (वर्क ऑर्डर) की कमी या रद्द हुए कार्य आदेश. स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं सभी क्षेत्रों में तीसरी सबसे आम बाधा थी, और विशेष रूप से उन दो क्षेत्रों के लिए जहां कामगारों को सार्वजनिक स्थान पर काम करना पड़ता है- फुटपाथ विक्रय और कचरा उठाना.

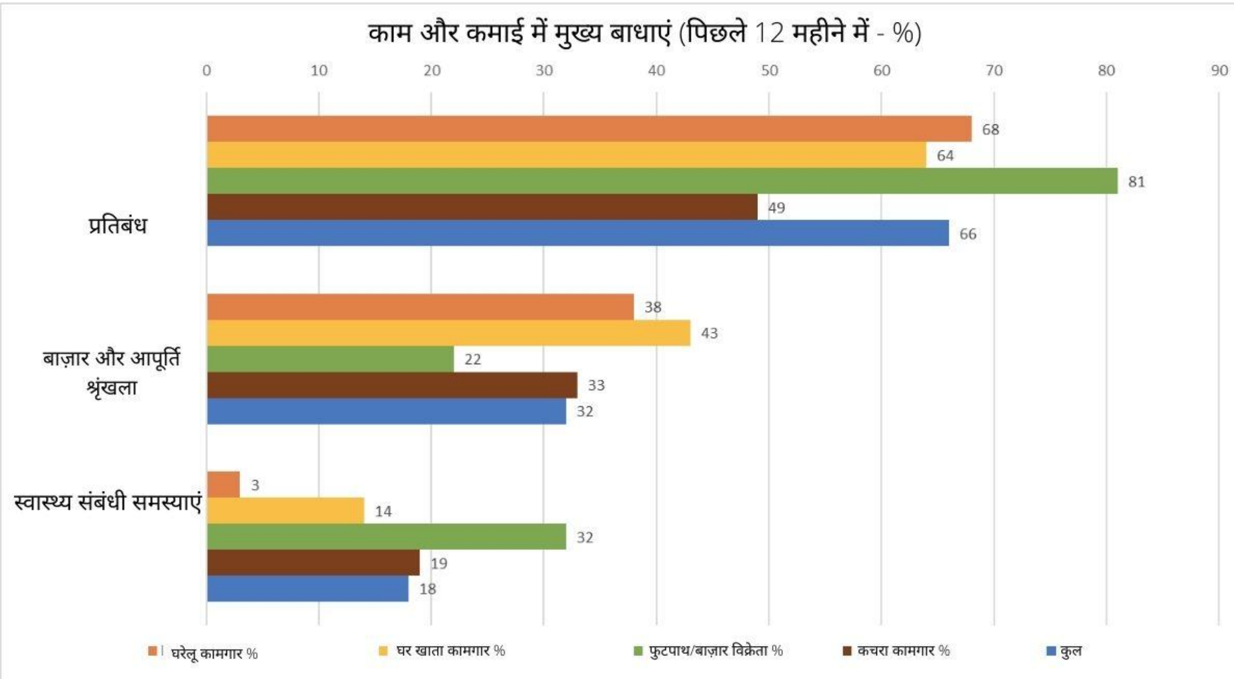

"हमारा काम बुरी तरह प्रभावित हुआ है. पहले हम बिना कोई क़र्ज़ लिए भी अपने परिवार का भरण पोषण करने लायक पर्याप्त कमा लेते थे लेकिन अब हमारी स्थिति बदल गई है. एक पैसा खर्च करने से पहले हमें दो बार सोचना पड़ता है. हम चाहते हैं कि हमारा काम फिर से शुरू होकर पहले की तरह हो जाएगा." - पुरुष फुटपाथ विक्रेता

"क्या सरकार ने कभी कूड़ा बीनने वालों की मदद की? उन्होंने हमें तितर-बितर करने के लिए पुलिस का इस्तेमाल किया, हम पर फर्जी चोरी और मनगढ़ंत आरोप लगाए. उन्होंने हमें परेशान करने और हमारा सामान जब्त करने के लिए पुलिस बलों का इस्तेमाल किया."- पुरुष कचरा कामगार

आय[7]

आय की रिपोर्टिंग के लिए, इस खंड में औसत के बजाय माध्यिका (मीडियन) को माप के तौर पर उपयोग किया गया है. ऐसा इसलिए क्योंकि आय में काफ़ी विविधता है (एक ही क्षेत्र के कामगारों के बीच भी). इस संदर्भ में, मीडियन आय सैंपल का बेहतर तरीके से प्रतिनिधित्व करती हैं, क्योंकि वे चरम मूल्यों (उच्च और निम्न दोनों) के प्रति कम संवेदनशील हैं.

कुल मीडियन आय (चारों क्षेत्रों में) वापस पूर्व-कोविड स्तरों पर नहीं पहुंच पाई है, हालांकि 2020 के बाद से काफी सुधार हुआ है. अप्रैल 2020 में जब पहला लॉकडाउन चरम पर था, और मध्य-2020, दोनों बार कामगारों की मीडियन कमाई शून्य थी. एक साल बाद, मध्य-2021 में, मीडियन कमाई बढ़कर पूर्व-कोविड स्तर के 57% तक पहुंच गई है. हालांकि, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि महामारी से पहले भी, चारों सर्वेक्षण क्षेत्रों में असंगठित कामगार आमतौर पर निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से कम कमाते थे[8]. बढ़ती मुद्रास्फीति (inflation) के चलते आवश्यक वस्तुओं की आसमान छूती कीमतों [9] ने महामारी पूर्व स्तर तक भी कमाई ना कर पाने की दिक्कत को और बढ़ा दिया है , जिसके परिणामस्वरूप जीवन यापन की लागत में वृद्धि हुई है.[10]

"अब सब कुछ महंगा है... जरा पेट्रोल-डीजल के रेट देखिए. रसोई चलाने के लिए हमें गैस की जरूरत है... वो खर्चे भी बढ़ रहे हैं... और हमारा प्रति पीस रेट कम हो रहा है... हम बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन हमारी कमाई कम हो रही है…" - महिला घर-खाता कामगार

	महामारी पूर्व [11] मीडियन कमाई का %, 2021 में
घरेलू कामगार	25%
घर-खाता कामगार	0
फुटपाथ विक्रेता	100%
कचरा कामगार	72%

[7] सभी आय डेटा में R2 उत्तरदाता शामिल हैं, जिन्होंने पूरी तरह से काम करना बंद कर दिया है और/या वे उत्तरदाता जो पिछले महीने में काम नहीं कर रहे थे, उनके काम के दिन और आय 0 पर स्थित हैं. आय के सारे आंकड़ों को सकल आय के रूप में रिपोर्ट किया गया है और इसमें माल खरीदने की लागत या अन्य इनपुट नहीं शामिल है. कमाई के आंकड़ों में केवल वही शामिल है जो व्यक्ति ने अपने प्राथमिक व्यवसाय से कमाया है, अन्य स्रोतों से नहीं.

[8]न्यूनतम मजदूरी दरों को दिल्ली सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाता है और समय-समय पर संशोधित किया जाता है. वर्तमान में प्रचलित दरों सहित हालिया अधिसूचनाएं यहां देखी जा सकती हैं: https://labour.delhi.gov.in/content/current-minimum-wage-rate . यहां तक कि महामारी से पहले के दौर में सर्वेक्षण किए गए असंगठित कामगारों की औसत आय 10,000 रुपये से कम थी, जो उस समय के 'अकुशल' कामगारों के लिए स्थापित मजदूरी दर से कम थी.

[9]'बढ़ती कीमतें कोविड-पस्त भारत को और भी झुलसा रही हैं, मैडम वित्त मंत्री'. (29 मई, 2021). न्यू इंडियन एक्सप्रेस. https://www.newindianexpress.com/business/2021/may/29/rising-prices-are-singeing-covid-battered-india madame-finance-minister-2309150.html पर उपलब्ध

[10]सिंह, आरके एट अल. (9 जून, 2021). 'महामारी के बीच, आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि ने आम लोगों के लिए जीवन कठिन बना दिया है'. इंडिया टुडे. https://www.indiatoday.in/india/story/pandemic-spike-prices-ential-items-difficult-common-people-1812561-2021-06-09 पर उपलब्ध

[11]फरवरी 2020

कुल	57%

कोविड-19 से पहले भी, घर-खाता कार्य सबसे कम कमाई का क्षेत्र था. महामारी के दो साल बाद, आजीविका का नुकसान भी इसी क्षेत्र में सबसे ज्यादा है. 57% घर-खाता कामगार बताते है कि मध्य-2021 में उनकी आय शून्य है. ये मध्य-2020, जब 76% ने शून्य आय की सूचना दी थी की तुलना में मामूली सुधार है. इससे पता चलता है कि घर-खाता कामगारों के हमारे अधिकांश सैंपल के लिए, कोई भी रिकवरी नहीं हुई है. उल्लेखनीय है कि यह तब है जब सैंपल विशेष रूप से सेवा (SEWA) दिल्ली संघ की सदस्यता से लिया गया है, जो वर्क ऑर्डरों की बहाली और मास्क बनाने जैसे नए अवसर पैदा के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं. समय-समय पर जिन्हें काम मिला भी, उन घर-खाता कामगारों ने बताया कि कि वे सप्ताह में कम दिन काम कर रहे हैं, और स्थानीय और वैश्विक बाजारों में मंदी के कारण पीस दरें कम बनी हुई है.

कोविड-19 से पहले घरेलू काम दूसरा सबसे कम कमाई वाला क्षेत्र था और यहां भी महामारी के दौरान कमाई में भारी गिरावट आई है. जैसा कि पहले राउंड के हमारे निष्कर्षों में बताया गया, 2020 के मध्य तक, जब पहले लॉकडाउन प्रतिबंधों में ढील दी गई, सर्वेक्षण में शामिल आधे से भी कम घरेलू कामगार काम फिर से शुरू करने में सक्षम थे. मध्य-2021 में, 63% घरेलू कामगार अब काम पर वापस आ गए हैं और कमाई में सुधार होना शुरू हो गया है, भले ही मामूली रूप से: इस क्षेत्र की महिलाओं ने जो मीडियन आय रिपोर्ट की, उसके अनुसार मध्य 2021 में उनकी कमाई फरवरी 2020 के मुकाबले एक चौथाई है. कामगारों ने कमाई के इस नुकसान के लिए कई कारणों का हवाला दिया, जिसमें प्रति सप्ताह औसत कार्य दिवसों में गिरावट और काम देने वाले परिवारों की संख्या में कमी शामिल है. इसके अलावा कामगारों ने बताया कि उनकी मोलभाव करने की शक्ति में काफी कमी आई है, नियोक्ता अब कम वेतन में अधिक काम की मांग करते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि ऐसे और भी लोग हैं जो काम की तलाश में हैं और कम दरों में काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे. जैसा कि SEWA के एक घरेलू कामगार नेता ने कहा, " हम इतने लंबे समय से काम कर रहे हैं, हम बाजार-दर जानते हैं ... जो नए हैं वे जागरूक नहीं हैं ... और वे पूछते भी नहीं हैं ... वे कम पैसे में काम करते हैं...तो अगर नियोक्ता कम पैसे में अपना काम करवा रहे हैं तो वे हमें क्यों रखेंगे?"

कचरा कामगार औसतन प्रति सप्ताह कम दिन काम कर रहे हैं, और महामारी से पहले की तुलना में कम कमा रहे हैं.महामारी से पहले कचरा कामगार जितना कमा रहे थे, मध्य-2021 में उसका तीन चौथाई कमा रहे हैं. इसके अलावा, कामगारों ने साक्षात्कार में बताया कि 2021 में उनके द्वारा एकत्र किए गए अपशिष्ट पदार्थों की कीमतों में वृद्धि (2020 में जो गिर गई थी) के बावजूद कमाई में गिरावट आई है, क्योंकि अब कचरे तक पहुंचने के लिए पहले की तुलना में और भी ज्यादा बाधाएं खड़ी हो गई है. सबसे बड़ी बाधा है छँटाई और पृथक्करण करने के लिए जगह की कमी, जिसके परिणामस्वरूप मूल्यवान सामान, जो पहले कबाड़ डीलरों को बेचा जाता था, वो अब बर्बाद हो जाता है. निवासी कल्याण संघ (रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (RWA)) और नगर पालिका, दोनों के द्वारा छँटाई की जगह तक पहुंचने पर रोक लगाई जाती है. निवासी कल्याण संघ घर-घर जाकर कचरा कामगार को कॉलोनियों के भीतर छँटाई करने की अनुमति नहीं देते, और नगर पालिका ने महामारी के दौरान छँटाई के लिए उपयोग किए जाने वाले कई सुविधा स्थानों को बंद कर निजी कंपनियों को सेवा-प्रदान करने के लिए ठेके पर दे दिया है.

महामारी से पहले फुटपाथ विक्रय सबसे अधिक कमाई करने वाला क्षेत्र था और लॉकडाउन प्रतिबंधों के चलते इस क्षेत्र में कमाई का भारी नुकसान हुआ है. मध्य-2020 में लॉकडाउन प्रतिबंधों में छूट मिलने के बावजूद बड़े वाणिज्यिक क्षेत्र और पड़ोस के साप्ताहिक बाजार बंद रहे, जिसके चलते इस क्षेत्र में मीडियन कमाई शून्य रही. मध्य-2021 में किए गए दूसरे राउंड के सर्वे में, इस क्षेत्र में मीडियन आय कोविड-19 पूर्व स्तर तक आ गई है. हालांकि, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि दिल्ली में सर्वेक्षण, सितंबर 2021 में

हुआ था, जब शहर में कोविड रोगियों की संख्या बेहद कम थी और इसलिए सभी बाजारों को पूरी क्षमता से संचालित करने की अनुमति दी गई थी. यह वक्त दिल्ली में त्योहारों के मौसम का होता है और आमतौर पर बाजारों में मांग में तेजी देखी जाती है. MBO साझेदारों और जमीनी कार्यकर्ताओं ने इस आंकड़े को और बारीकी प्रदान की. उन्होंने समझाया कि भले ही सितंबर में कमाई कोविड पूर्व स्तर पर थी लेकिन फुटपाथ विक्रेताओं को 2020 के बाद से बहुत अनिश्चितता और अस्थिरता का सामना करना पड़ा, क्योंकि जब भी संक्रमण की दर में इजाफा हुआ, आवागमन पर बारंबार पाबंदी लगाई गई और बाजार बंद कर दिए गए. इसके अलावा, कई कामगारों ने पर्यटन के आकर्षण स्थल , सार्वजनिक परिवहन बिंदुओं और अन्य प्रमुख केंद्रों के बंद होने के कारण ग्राहकों की मांग में कमी की सूचना दी. इसके चलते विक्रेताओं को उतनी ही रकम कमाने के लिए ज़्यादा समय तक काम करना पड़ा. मुद्रास्फीति (inflation) के कारण इनपुट लागत में भी वृद्धि हुई है, उदाहरण के लिए फुटपाथ विक्रेताओं पर गैस की कीमतों में वृद्धि का बहुत असर पड़ा है.

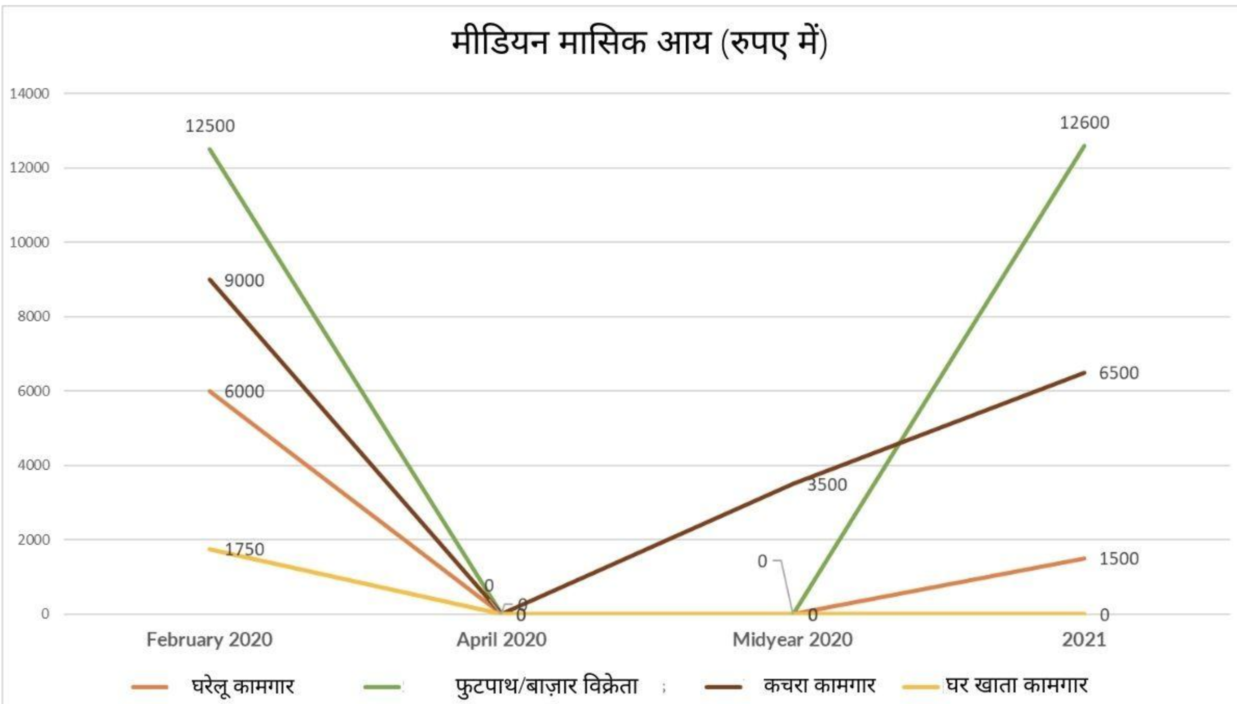

कमाई के नुकसान के भी सरासर लैंगिक पहलू हैं. जैसा कि ऊपर ग्राफ में देखा जा सकता है, महामारी से पहले भी घर-खाता काम और घरेलू काम सबसे कम कमाई वाले क्षेत्र थे. ये महिला-प्रधान क्षेत्र हैं और हमारे सर्वेक्षण में सभी महिला सैंपल मध्य-2021 में सबसे निचले स्तर की कमाई दर्ज कर रहे है. यहां तक कि कचरा और फुटपाथ विक्रय क्षेत्रों में, जहां सैंपल में पुरुष और महिला, दोनों शामिल थे, फरवरी 2020 में महिलाएं पुरुषों की तुलना में कम कमा रही थी, और यह अंतर अब तीन गुना बढ़ गया है. मध्य-2021 में, जबकि पुरुष कचरा कामगार की मासिक आय महामारी से पहले के स्तर के बराबर है, वहीं महिलाओं की कमाई महामारी पूर्व स्तर तक नहीं आ पाई है. चूंकि दिल्ली में कचरा बीनने वाली ज्यादातर महिलाएं या तो अपने पारिवारिक रोज़गार को आगे बढ़ा रही होती हैं, या छोटे गोदामों में निजी कबाड़ डीलरों के यहां नौकरी कर रही होती हैं, इसलिए यह दर्शाता है कि इस क्षेत्र में रिकवरी असमान रही है. इसी तरह, महिला विक्रेता जो महामारी से पहले भी पुरुष विक्रेताओं से कम कमा रही थी, अभी भी बदतर स्थिति में हैं और अपने पुरुष समकक्षों की तुलना में मीडियन मासिक आय में अधिक नुकसान दर्ज कर रही है.

आय की हानि घरेलू स्तर पर भी परिलक्षित होती है. यदि हम घरेलू मासिक आय को लें, तो भी 70% कामगारों ने 2021 में कोविड-पूर्व स्तर से कम घरेलू आय दर्ज कराई. आम तौर पर, परिवार के अन्य सदस्य भी उसी या अन्य असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, और सभी असंगठित क्षेत्र संकट से प्रभावित हुए हैं. स्थानीय व्यवसाय और अन्य उद्योग भी संकट से गुजर रहे हैं, इसलिए बड़े पैमाने पर लोगों की छँटनी हुई है. क्षेत्रवार देखें तो, घर-खाता कामगारों (81%) ने घरेलू आय में सबसे अधिक हानि अनुभव की.

भोजन सुरक्षा

दिल्ली में असंगठित कामगारों के बीच काम और कमाई का नुकसान कई लोगों के लिए भोजन असुरक्षा के रूप में उजागर हुआ. वर्ष 2021 के मध्य में भी 29% कामगारों ने सूचना दी कि पिछले महीने उनके घर के वयस्कों को भूखा रहना पड़ा. 25% उत्तरदाता, जिनके घर में बच्चे थे, उन्होंने बताया कि उनके घर में बच्चों को भी भूखा रहना पड़ा. पांच में से दो उत्तरदाताओं (44%) ने कहा कि उनको या घर के अन्य सदस्यों को, पिछले महीने एक वक्त का भोजन छोड़ना पड़ा या अपनी पसंद से कम किस्म के भोजन पदार्थों से काम चलाना पड़ा. ये विशेष रूप से परेशान करने वाली बात है क्योंकि अधिकांश कामगारों ने बताया कि उन्हें सरकार या नागरिक समाज से भोजन सहायता प्राप्त हुई, जैसा कि राहत वाले अनुच्छेद में चर्चा की गई है. आमतौर पर, ऐसी राहत केवल अत्यधिक तनाव की अवधि के दौरान प्रदान की गई, जैसे कि जब लॉकडाउन लगाया गया था. हालांकि, यह देखते हुए कि रिकवरी सिलसिलेवार नहीं है, असंगठित कामगारों को नियमित और दीर्घकालिक आधार पर भोजन राहत की आवश्यकता है.

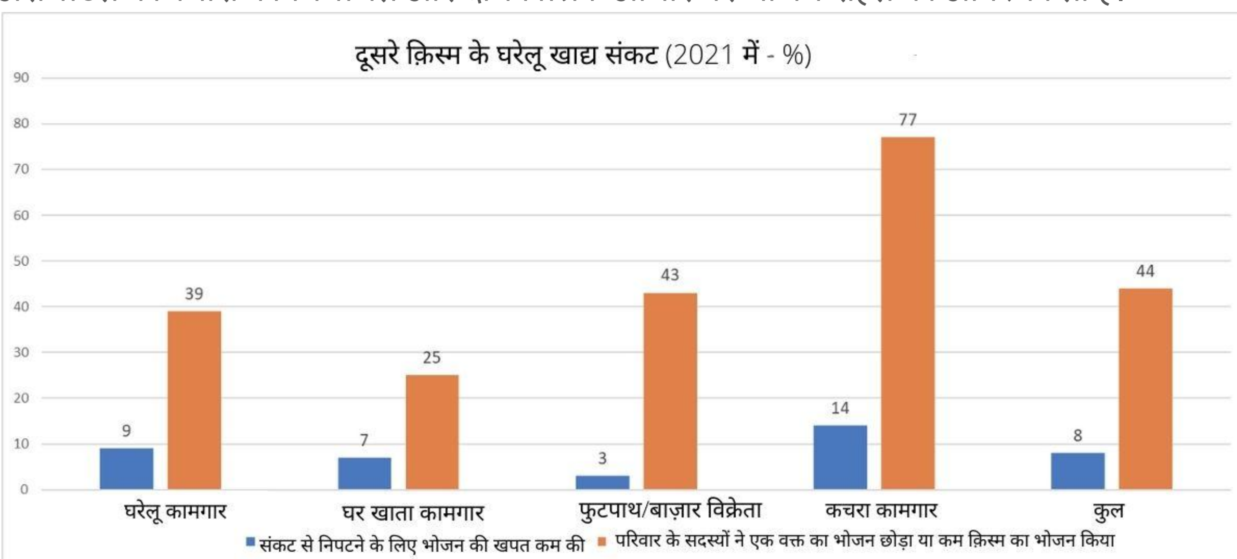

> “कोई कमाई नहीं होने से, हमें परिवार का भरण-पोषण करना बहुत मुश्किल हो रहा है. बच्चों को भूखा रहना पड़ता है. हमें अलग-अलग जगहों से खाना लाना पड़ता है, हम नहीं जानते कि कितने दिनों तक हम बाहर से खाना हासिल कर सकेंगे.” - कचरा बीनने वाली महिला

स्वास्थ्य और सुरक्षा

ख़ास तौर पर अप्रैल से मई 2021 में कोविड की दूसरी लहर को सम्मिलित किया जाए तो, कोविड -19 के मरीजों और मौतों की उच्च दर के मामले में दिल्ली भारत में सबसे अधिक प्रभावित शहरों में से एक रहा है. हालांकि, सितंबर 2021 में हमारे सर्वेक्षण में, केवल 7% उत्तरदाताओं ने कहा कि पिछले 12 महीनों में उनके या उनके घर के किसी सदस्य का कोविड टेस्ट में पॉजिटिव परिणाम आया है, और केवल 5 प्रतिशत लोगों ने कहा कि उन्हें COVID-19 के कारण अपने या परिवार के किसी सदस्य की देखभाल के लिए काम से छुट्टी लेने की आवश्यकता पड़ी. इस डेटा को इस चेतावनी के साथ प्रस्तुत किया गया है कि लांछन और बीमारी से जुड़े बाकी डरों के कारण कम रिपोर्टिंग होने की संभावना है. कई कामगारों ने यह भी स्वीकारा कि ज्यादा कीमत, संक्रमण के चरम के दौरान टेस्ट की अनुपलब्धता और भीड़-भाड़ वाले अस्पतालों में जाने के डर के कारण कोविड -19 टेस्ट कराना अक्सर उनके लिए मुश्किल रहा.

2021 के मध्य में, जिन उत्तरदाताओं ने पिछले महीने काम किया, उनमें से 94% से व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) के उपयोग की जानकारी दी. घर खाता कामगारों ने पीपीई का सबसे कम उपयोग किया (73%), संभवत इसलिए कि उनका घर ही उनका कार्यस्थल था. सर्वे में हर पांच में से चार (79%) उत्तरदाताओं ने स्वयं पीपीई खरीदे. 18 प्रतिशत लोगों ने अपने एमबीओ या एक चैरिटेबल संस्थान से पीपीई प्राप्त किया, और केवल 10% ने इसे अपने नियोक्ताओं से प्राप्त किया. यहां तक कि घरेलू कामगार जो अपने नियोक्ता के घरों में काम करते हैं, उन्हें इस मामले में ज्यादा सहयोग नहीं मिला, केवल एक चौथाई (28%) उत्तरदाताओं ने बताया कि उनके नियोक्ताओं ने उन्हें पीपीई किट प्रदान किया है.

"मैंने मास्क पहना, अपने साथ एक हैंडवाश और एक सैनिटाइज़र रखा. मैंने यह सुनिश्चित करने के लिए सभी सुरक्षा उपाय किए ताकि कोई परेशानी न हो या मैं बीमार न पड़ूं. यहां तक कि जब लोग दुकान पर आते थे तो मैं उनसे बहुत दूर खड़ी हो जाती थी और दुकान के बाहर एक रस्सी लगा देती थी ताकि ग्राहकों को पता चल जाए कि उन्हें कुछ दूरी बनाकर रखनी है. - महिला फुटपाथ विक्रेता

*"मैं एक महीने में मास्क, सैनिटाइज़र और साबुन जैसी चीजों के लिए कम से कम **500** से **600** रुपए खर्च करती हूं. इसलिए अगर मैं **8000** रुपये कमाती हूं, तो मुझे यह सब खरीदने के लिए **1000** रुपए की बचत करनी होगी, क्योंकि यह जीवित रहने के लिए जरूरी है. "- महिला घरेलू कामगार*

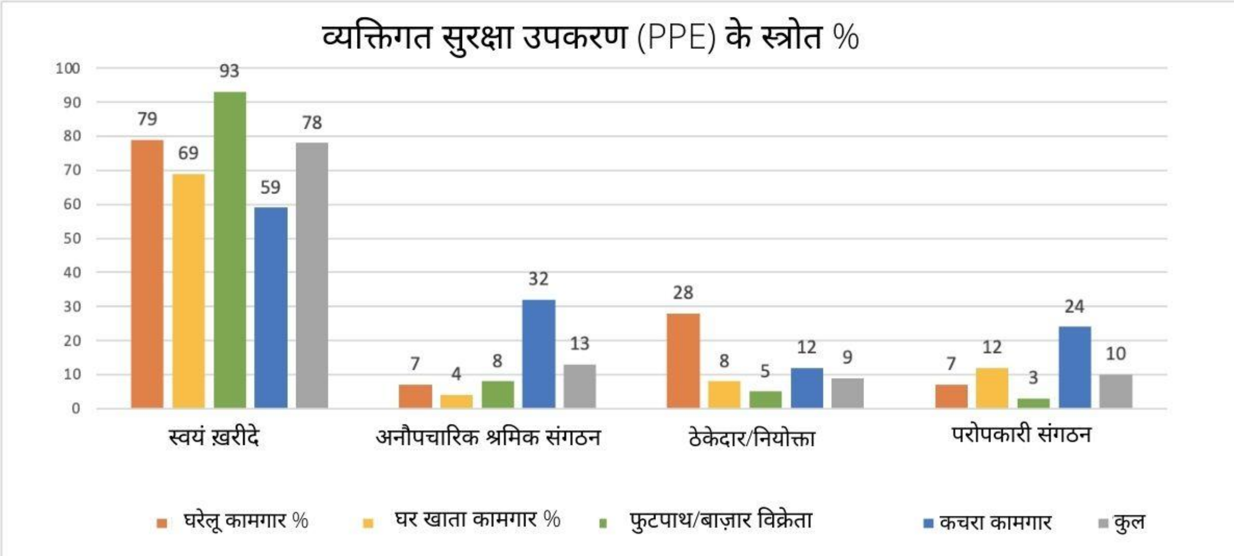

* उत्तरदाता एक से अधिक उत्तर चुन सकते हैं

भारत ने स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और 45 वर्ष से अधिक उम्र के बुज़ुर्गों को प्राथमिकता देते हुए चरणबद्ध तरीके से 16 जनवरी, 2021 को कोविड-19 टीकाकरण शुरू किया. 1 मई से, 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए टीकाकरण कार्यक्रम शुरू हुआ. शुरुआत में, असंगठित कामगारों को सरकारी केंद्रों पर टीके की मुफ़्त खुराक की अनुपलब्धता, प्राइवेट अस्पतालों में इसकी ज्यादा कीमत और वेबसाइट पर पूर्व-पंजीकरण की जरूरत के कारण आई तकनीकी दिक्कत के चलते टीकाकरण के लिए संघर्ष करना पड़ा. हालांकि, समय के साथ, अधिक सरकारी केंद्र खोले गए और हमारे सर्वेक्षण में, 93% उत्तरदाताओं को या तो वैक्सीन की कम से कम एक डोज़ मिल गई थी या अगले चार हफ्तों में दी जानी थी. हालांकि ध्यान रहे कि सर्वे के लिए लिया गया ये सैम्पल उन कामगारों का है जो ऐसे मजबूत एमबीओ से जुड़े हैं जिन्होंने वैक्सीनेशन के बारे में जागरूकता बढ़ाने और कामगारों को वैक्सीनेशन की सुविधा दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. हालांकि, टीकाकरण अभियान में क्षेत्रीय, लैंगिक और सामाजिक असमानताओं को [12]दर्शाने वाली कई रिपोर्टें आई हैं, और वास्तव में एनसीआर इलाक़ा, जहां दिल्ली स्थित है, वहां पुरुषों की तुलना में महिलाओं की टीकाकरण की दर कम है.

खुले छोर वाले सवालों और गुणात्मक साक्षात्कारों में, कई कामगारों ने बीमारी के चलते अपना भय और तनाव व्यक्त किया, जिससे वे अभी भी चिंतित हैं.

"हालांकि परिवार में कोविड *-19* से किसी की मृत्यु नहीं हुई , लेकिन कोविड-पॉजिटिव होने का बड़ा डर था, जिसके चलते हम लगातार डर में जिए. इस साल स्थिति पिछले साल से भी खराब थी और लंबे समय तक हमें अपना काम छोड़ना पड़ा. साथ ही पुलिस मास्क न पहनने पर भारी जुर्माना लगा रही थी, हम शुरू में मास्क नहीं खरीद पा रहे थे इसलिए जुर्माना वहन करना असंभव था. "- कचरा कामगार

"मुख्य चिंता यह थी कि यदि मुझे कोविड-*19* हो गया तो मेरे परिवार का क्या होगा, क्योंकि मुझे उप-ठेकेदारों से मिलना पड़ता है और काम के लिए सामान इकठ्ठा करना होता है. चूंकि यह हवा के माध्यम से आसानी से फैलने वाली बीमारी है और लोग कहते हैं कि इसका वायरस किसी सतह पर एक घंटे से अधिक समय तक जीवित रह सकता है. क्या होगा अगर कारखाने में कपड़े का कोई पीस कोई कोरोना से पीड़ित व्यक्ति पकड़ ले, जब उसी टुकड़े पर मैं काम करूंगी तो मैं भी संक्रमित हो जाऊंगी, इसलिए उस पीस पर काम करना मेरे लिए

[12]एस्टेव्स, एलए और इकबाल, एन. (3 नवंबर, 2021) '1 बिलियन वैक्सीन डोज़, बट, वुमेन ट्राइबल्स लैग'. इंडिया स्पेंड पर उपलब्ध: https://www.indiaspend.com/covid-19/1-billion-vaccine-doses-but-women-tribals-lag-785262

थोड़ा डरावना था. लेकिन अब में वैक्सीन लगवा चुकी हूँ इसलिए डर कम है." -महिला घर-खाता कामगार

घरेलू तनाव

देखभाल और अन्य घरेलू जिम्मेदारियां

स्वास्थ्य और आजीविका पर प्रभाव के साथ-साथ कोविड-19 महामारी के कारण देखभाल का संकट भी पैदा हो गया है. हमारे सर्वेक्षण में, 33% कामगारों ने बच्चों की देखभाल में और 31% कामगारों ने घर के बुजुर्गों की देखभाल में ज्यादा समय खर्च होने की सूचना दी. कई उत्तरदाताओं ने फरवरी 2020 की तुलना में पिछले महीने खाना पकाने (14%) और सफाई (24%) पर ज्यादा समय खर्च होने की सूचना दी. आधे से अधिक उत्तरदाताओं (55%) ने यह भी बताया कि इन जिम्मेदारियों के कारण वे या तो काम पर नहीं जा सके या महामारी से पहले फरवरी 2020 की तुलना में उनके लिए काम करना मुश्किल हो गया. पुरुषों (38%) की तुलना में कहीं अधिक महिलाओं (62%) ने ऐसा कहा. पांच में से दो से ज्यादा उत्तरदाताओं, जिनमें 50 प्रतिशत पुरुष और 25% महिलाएं थीं, उन्होंने बताया कि देखभाल की जिम्मेदारियों के कारण वे महामारी के पहले की तुलना में कम घंटे काम कर पाए.

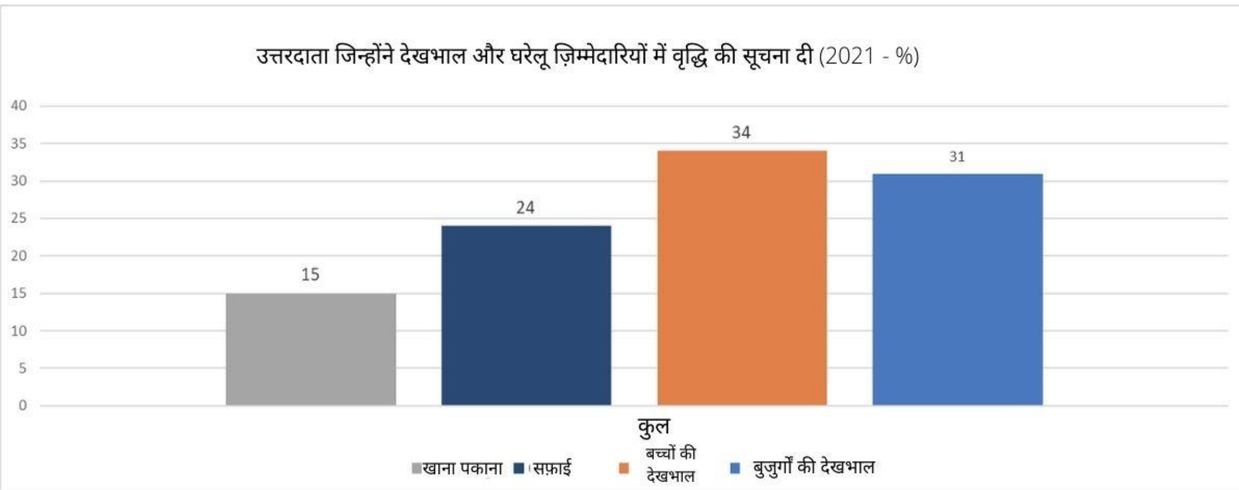

* सैंपल में केवल वे उत्तरदाता शामिल हैं जिन्होंने अपने घरों में रहने वाले बच्चों और/या बुजुर्गों की सूचना दी. इस सैंपल में वे घरेलू कामगार शामिल नहीं हैं जो अपने नियोक्ता के घर में रहते हैं.

घरेलू चिंताएं और तनाव

असंगठित कामगार, कम आय, आजीविका की असुरक्षा, लगातार भूख और सरकारी नियमों के कारण लगाई गईं बाधाओं जैसी समस्याओं के साथ रह रहे हैं, जिसके चलते इनके घरों में तनाव और भय का वातावरण बन गया है. कई उदाहरण हैं जहां कामगारों और/या उनके पति/पत्नी की नौकरी चली गई, जिससे उन घरों की स्थिरता को आघात पहुंचा जो इस संकट के पहले भी तनख्वाह दर तनख्वाह अपना गुजारा चला रहे थे. कई कामगारों ने बताया कि घर का किराए ना चुका पाना, उनके तनाव की एक ख़ास वजह है और इसलिए उन्हें चिंता है कि वो अपने रहने की जगह खो देंगे.

कामगारों ने बताया की मुश्किलों से मुकाबला करने के लिए जो और फैसले लेने पड़े, जैसे कि केवल बुनियादी ज़रूरतें पूरी करने की क्षमता होना, बच्चों के लिए कम भोजन उपलब्ध होना और उनकी शिक्षा से समझौता करना, चिंता के अन्य प्रमुख स्रोत थे. आजीविका के नुकसान के कारण स्कूल की फीस का भुगतान करना कठिन हो गया है. जिसके कारण कई अभिभावकों को या तो अपने बच्चों को उच्च गुणवत्ता वाले निजी स्कूलों से निकालकर सरकारी स्कूलों में दाखिला दिलाना पड़ा, या उनकी पढ़ाई पूरी तरह रोक देनी पड़ी. कई लोगों ने ऑनलाइन कक्षाओं के लिए इंटरनेट तक पहुंच सहित मोबाइल फोन मिल पाने की दिक्कत भी बताई. हालांकि ऑनलाइन क्लास लेने के बावजूद भी उन्हें इस बात की चिंता है कि बच्चे उचित मार्गदर्शन के बिना कितना सीख पा रहे हैं.

कामगारों में भी इस बीमारी को लेकर अधिक भय इसलिए था क्योंकि उन्हें आजीविका के लिए लगातार बाहर जाने का ख़तरा उठाना पड़ता था. विशेष रूप से, कचरा कामगार और घरेलू कामगारों ने तनाव की कई कहानियां बताईं, चाहे वह दूषित अपशिष्ट पदार्थों से निपटना हो या उन नियोक्ताओं द्वारा काम पर बुलाया जाना, जिन्होंने वायरस से संक्रमित होने का खुलासा नहीं किया था. इसके अलावा, उन पर लांछन लगाया जा रहा था कि वही बीमारी के वाहक हैं.

इस सबमें कामगारों की अपने भविष्य को लेकर चिंता और सरकार की तरफ़ से अलग-थलग किए जाने की भाव भी शामिल था. सरकारी कार्य व्यवस्था में उदासीनता और विश्वास की कमी बढ़ रही ह,. जैसा कि कामगारों ने बताया कि वे अपनी आजीविका कमाने की कोशिश करते हैं और बजाय सहयोग के उन्हें उत्पीड़न और बेदखली का सामना करना पड़ता है.

> *“* मार्च ***2020*** से अब तक घर का किराया बकाया है*...* ***8*** महीने का किराया दे दिया है*...*मुझे अपनी कमाई से इस महीने का किराया भी देना है*...*अभी भी ***6*** महीने का घर का किराया बकाया है*...”* **-**घर**-**खाता महिला कामगार
>
> *“*मेरे पति को कोविड ***-19*** के कारण दिल का दौरा पड़ा और अब वह काम नहीं कर पा रहे हैं*.* अब मैं घर में अकेली कमाने वाली सदस्य हूं*.* मैंने अपने बच्चों का स्कूल भी छुड़वा दिया है*. “***-** महिला घरेलू कामगार
>
> *“*हमें अपने बेटे को निजी स्कूल से निकाल कर सरकारी स्कूल में दाखिला दिलाना पड़ा*.* हमने किराए का भुगतान भी नहीं किया है*. ”***-** घर**-**खाता महिला कामगार
>
> *“*मेरी बेटी एक सरकारी स्कूल में है*,* लेकिन मेरा बेटा जो एक निजी स्कूल में है*,* मुझे अभी उसकी पूरे साल की फीस देनी है*.* इसलिए उन्होंने उसकी ऑनलाइन क्लास बंद कर दी है और अब हमें फोन करना भी बंद कर दिया है*.* अगर मुझे स्कूल से बेटे का लीविंग सर्टिफिकेट भी लेना है*,* तो भी मुझे फीस देनी होगी*.* इसकी वजह से मेरे बेटे की पढ़ाई छूट गई और पूरा साल बर्बाद हो गया*.* **-** महिला फुटपाथ कामगार

राहत के उपाय

दिल्ली के असंगठित कामगारों के लिए कोविड की महामारी, स्वास्थ्य, आजीविका और देखभाल के तिहरे संकट के रूप में सामने आई. बीमारी रोकने के लिए उठाए गए सरकारी कदम कठोर उपायों पर आधारित थे. लोगों के जीवन-यापन के लिए जरूरी सेवाओं को बढ़ावा देने पर अधिक विचार नहीं किया गया. इन उपायों में असंगठित कामगारों की आजीविका की जरूरतों को अनदेखा किया गया. इस कारण देश के अन्य बड़े शहरों की तरह, दिल्ली में बड़े पैमाने पर प्रवासी कामगारों ने पलायन किया, जिनमें से कई कामगार हजारों मील पैदल चलकर अपने गांव गए.

सरकार द्वारा विशेष रूप से इस अध्ययन में शामिल चार क्षेत्रों के असंगठित कामगारों में से किसी के लिए भी कोई नकद अनुदान योजना शुरू नहीं की गई. केवल कुछ महिला कामगार जिनके पास जन-धन योजना के तहत बैंक खाते थे, उन्होंने अप्रैल, मई और जून 2020 के महीने में 500 रुपये मिलने की सूचना दी.

सरकारी राहत में भोजन सहायता सबसे महत्वपूर्ण थी, लेकिन इसकी प्रभावशीलता भी समय के साथ बदलती रही है. हमारे सर्वेक्षण के दूसरे दौर में, 65% उत्तरदाताओं ने बताया कि उन्हें पिछले 12 महीनों में सरकारी भोजन सहायता मिली, जबकि 2020 में पहले चरण के सर्वेक्षण में 73% कामगारों को भोजन सहायता मिली थी. भोजन सहायता योजना, जो लॉकडाउन के पहले चरण में शुरू हुई थी- जिनमें राशन कार्डधारकों के लिए मुफ्त या रियायती दरों पर राशन, प्रवासियों के लिए ई-कूपन योजना ताकि वो आधार कार्ड से राशन प्राप्त कर सकें, और सरकारी स्कूलों में पके हुए भोजन का वितरण आदि शामिल थे- बीमारी की दूसरी लहर और अप्रैल से मई 2021 में लॉकडाउन के दौरान उसी स्तर पर क्रियान्वयित नहीं की गई[13]. पिछले वर्ष की तुलना में कामगारों के अपने संगठनों और समाज से मिलने वाली राहत भी कम हो गई क्योंकि चिकित्सकीय आपूर्ति की वो वस्तुएं जिनकी कमी थी, उनकी खरीद की जाने लगी, जैसे कि ऑक्सीजन, अस्पताल के बेड और जरूरी दवाएं. हालांकि, कामगारों से खुले सवालों के जवाब में पता चला कि पिछले साल कई महीने उन्हें राशन के रूप में उनके एमबीओ ने महत्वपूर्ण सहयोग दिया. कामगार संगठनों ने भी लाभार्थियों की पहचान, दस्तावेज़ीकरण, आवश्यकता पड़ने पर पंजीकरण कराने, और जानकारी देने जैसे काम सुनिश्चित करके सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.

"हमारे रेहड़ी-पटरी वाले यहां के नहीं हैं..वे दूसरी जगहों से आते हैं, उनके पास राशन कार्ड तक नहीं है....सरकार ने कहा कि अगर उनके पास दिल्ली में रहने का सबूत होगा, तो ही वे राशन के पात्र होंगे. हमारे संगठन ने, बाजारों के सभी प्रधानों (नेताओं) के माध्यम से, हर जरूरतमंद व्यक्ति को तीन बार राशन दिया...न कि एक बार...हमने टीकाकरण के लिए रजिस्ट्रेशन करने में उनकी मदद की...हम अब तक वैक्सीनेशन केंद्र स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं.."- फुटपाथ विक्रेता लीडर, जनपहल

"अकबर भाई ने बिल्कुल मुफ़्त में बच्चों के लिए दूध सहित किराने का सामान देकर मेरी मदद की. कोविड के समय में, वह हमारे लिए एक रक्षक की तरह थे. उन्होंने और बस्ती सुरक्षा मंच की टीम ने हमारे समुदाय के सभी बच्चों के लिए सुबह 9 बजे से 12 बजे तक एक स्कूल (ट्यूशन) शुरू किया. "- कचरा कामगार पुरुष

"बीवीडी ने मुझे भोजन राशन और किराने की वस्तुओं के साथ मदद की. उन्होंने मेरी बेटी जो कि 9वीं कक्षा में पढ़ रही है, उसके लिए मुझे एक फ़ोन भी दिया ताकि वह अपनी पढ़ाई जारी रख सके." - महिला घरेलू कामगार

[13] कुंदूरी, ईशा एट अल। (6 जून, 2021) "भोजन सुरक्षा नेट का विस्तार: दिल्ली, 2020 लॉकडाउन से सबक"। द वायर पर उपलब्ध:
https://thewire.in/rights/delhi-covid-19-lockdown-food-security-migrants

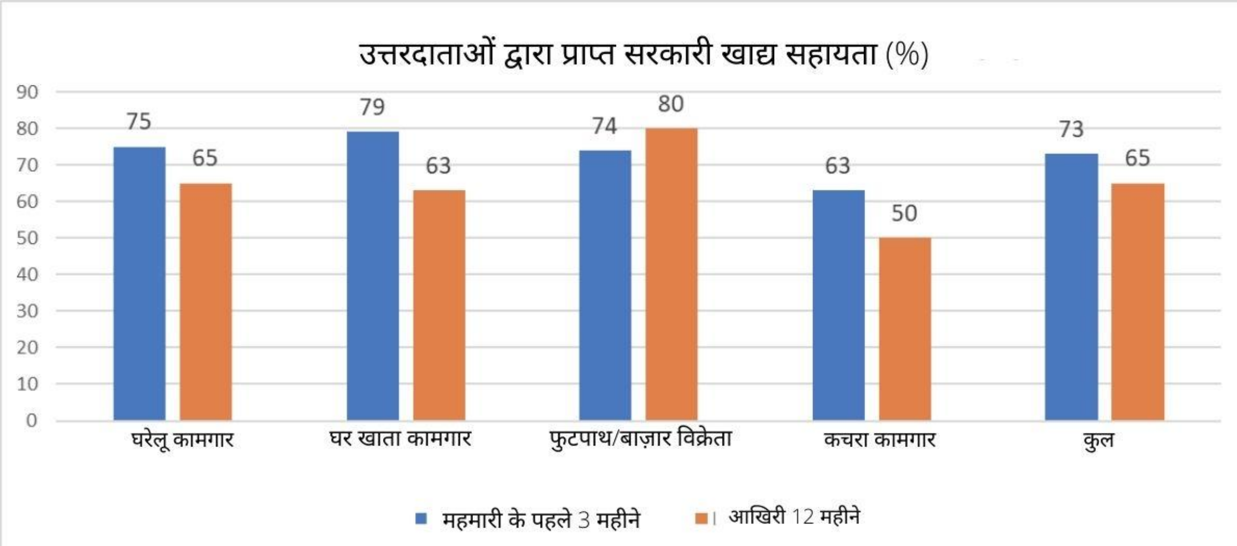

दस (13%) में से एक ज्यादा उत्तरदाताओं ने सरकारी ऋण मिलने की भी सूचना दी. मई 2020 में केंद्र सरकार ने रेहड़ी-पटरी वालों के लिए एक आर्थिक राहत योजना की घोषणा की. पीएम स्वनिधि योजना के तहत, एक फुटपाथ विक्रेता एक बार 10,000 रुपए का ऋण लेने के लिए पात्र है. हालांकि धीमा क्रियान्वयन, प्रमाण के लिए सर्टिफिकेट की ज़रूरत और बैंकों से जुड़ी समस्याओं का अर्थ है कि सभी वेंडर्स इसका लाभ नहीं उठा पाए. इसके अतिरिक्त, बड़े कर्ज के बोझ और बचत न होने के कारण, यह राशि काम को फिर से शुरू करने के लिए अपर्याप्त साबित हुई है [14] और इसका उपयोग अक्सर उपभोग की जरूरतों के लिए किया जाता था.

आधे से कम (46%) उत्तरदाताओं ने बताया कि उनका किराया, रोज़मर्रा के खर्च, पढ़ाई का खर्च या ऋण, रद्द, माफ या स्थगित कर दिया गया. 27% कामगारों ने कहा कि उन्होंने किराए का भुगतान नहीं किया है, और यह समस्या विशेष रूप से घरेलू कामगारों (54%) और घर-आधारित कामगारों (41%) के साथ अधिक थी. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि सरकार ने इसके लिए कोई नियम लागू नहीं किया बल्कि ये सब कुछ असंगठित सामाजिक नेटवर्क और मकान मालिकों और किरायेदारों के बीच असंगठित सामाजिक व्यवस्था चलते हुआ था.

"किराया देना मुश्किल था क्योंकि हमारे पास कोई काम नहीं था ...इसलिए कुछ मकान मालिकों ने हमसे केवल आधा किराया मांगा ... कुछ ने बिजली का बिल नहीं लिया. हमने सामूहिक रूप से मकान मालिकों के घर जाकर उनसे बात की, क्योंकि कई बहनें कहती थीं कि उनके पास किराया देने के लिए पैसे नहीं थे. हमने उन्हें बताया ताकि वे समझें कि बिना काम के महिलाएं उन्हें किराया दे पाने में सक्षम नहीं हैं. हमने आश्वासन दिया कि अगर वे किराए का एक हिस्सा अभी ले लें, तो जब महिलाओं को काम मिलेगा, वे बाकी किराए का भी भुगतान कर देंगी. - घरेलू कामगार नेता, सेवा

[14]मजीठिया, ए.एस. (2021) 'लॉकडाउन के प्रभाव के साथ अभी भी जारी है, दिल्ली फुटपाथ विक्रेताओं के दुःख ज्यों के त्यों". द वायर पर उपलब्ध है- https://thewire.in/labour/as-the-impact-of-lockdown-yet-to-wear-off-delhi-street-vendors-travails-persist

अनुकूलन और मुकाबला करने की रणनीतियां

जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, असंगठित कामगारों को सरकार या किसी अन्य औपचारिक प्रतिष्ठान से बहुत कम सहयोग मिला है. रोजगार और कमाई पर हो रहे प्रभाव को देखते हुए, कामगारों को अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए कई तरह के उपाय करने पड़े हैं. हमारे सर्वेक्षण में दस में से नौ (91%) उत्तरदाताओं ने बताया कि उन्होंने अपने परिवारों को संकट से बचने में मदद करने के लिए एक या एक से अधिक रणनीतियां अपनाई. जिनमें सबसे महत्वपूर्ण था कर्ज लेना और बचत को काम में लाना.

कुल मिलाकर, 73% कामगारों को किसी न किसी स्रोत से उधार लेना पड़ा. इस उधार का बड़ा हिस्सा परिवार (29%) या दोस्तों और पड़ोसियों (42%) से प्राप्त हुआ. पिछले 12 महीनों में कर्ज लेने वाले लोगों में, बकाया कर्ज की औसत राशि लगभग 12,000 रुपये है. हालांकि पूरी तुलना संभव नहीं है, लेकिन यह उल्लेख किया जाना चाहिए कि कोविड-पूर्व काल में भी, औसत मासिक कमाई इससे कम थी, सिर्फ़ 9000 रुपए. इसके अतिरिक्त, कई कामगारों ने 50,000 रूपए से 1,50,000 रूपए के बीच के बड़े कर्ज लेने की जानकारी भी दी. यह कर्ज चिकित्सकीय एवं शादियों जैसे आकस्मिक खर्चों को पूरा करने के लिए लिए गए थे.

लगभग एक तिहाई (30%) कामगारों ने भी कहा कि उन्हें अपनी बचत में से खर्च करना होगा. हालांकि, महामारी की शुरुआत के बाद से खर्च के लिए अपनी बचत में से धनराशि निकालने वालों में से 90% ने कहा कि उनके पास बचत को दोबारा पूरा करने की क्षमता नहीं है. इसका आशय ये है कि कामगारों और उनके परिवारों की संकट को वहन कर सकने की असमर्थता इन दो सालों से कई गुना बढ़ गई है.

*"*यह वास्तव में मेरे लिए बहुत कठिन था*,* मेरी बचत की पूरी रकम खर्च हो गई*.* मैंने अपने भाई से ***50000*** रूपए उधार लिए और मुझे अभी भी ***30000*** रूपए की बकाया राशि का भुगतान करना है*.* मैं अपने पूरे जीवन इस पेशे को जारी नहीं रख सकता इसलिए मैं कुछ और करने की सोच रहा था*.* हालांकि इस कोविड ***-19*** ने सब कुछ बदतर कर दिया है*. "* - कचरा कामगार पुरुष

*"*हमारे बच्चों को कोविड ***-19*** के कारण भूखा सोना पड़ा*.* हमें रोजमर्रा के बुनियादी खर्चे उठाने के लिए भी कर्ज लेना पड़ा*,* अब हम उन कर्जों को वापस नहीं कर पा रहे हैं*.* हम कर्ज कहां से लौटाएंगे क्योंकि हमारे पास अभी कोई काम नहीं है*. -*फुटपाथ विक्रेता पुरुष

*"*कोई काम नहीं है और हमारे मकान मालिक ने हमें किराए पर राहत नहीं दी जिसका भुगतान करने में हम असमर्थ थे*.* किराए का भुगतान न करने के कारण हमें निकाल दिया गया और हमें अपना घर बदलना पड़ा*. "* - घर खाता कामगार महिला

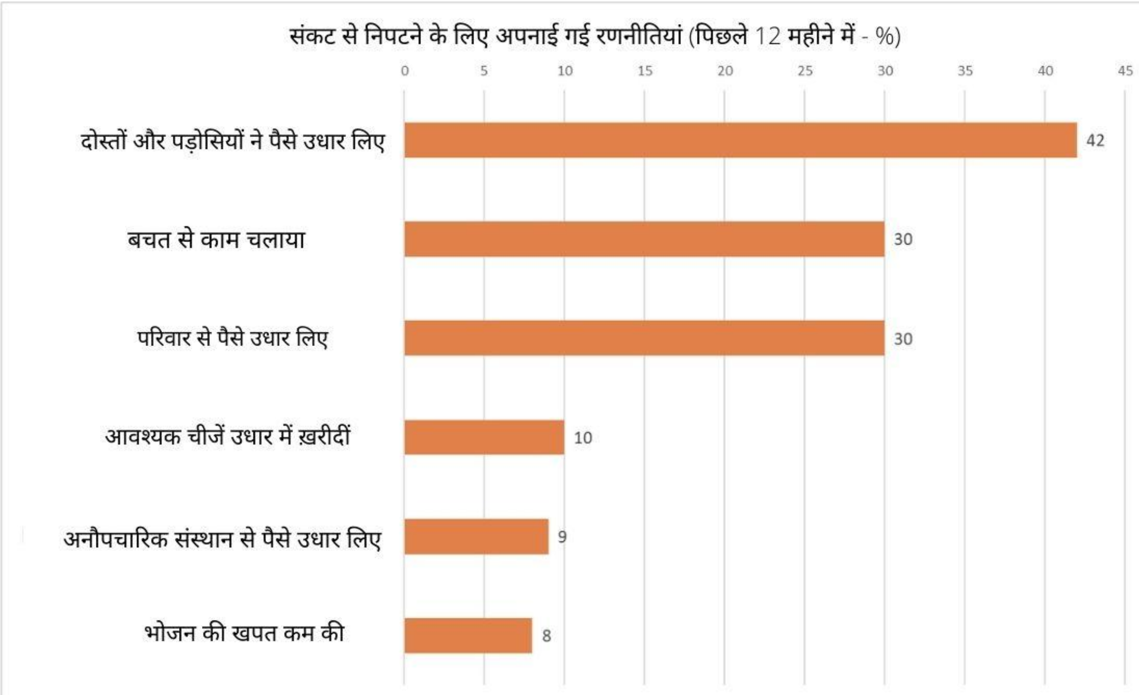

* उत्तरदाता एक से अधिक उत्तर चुन सकते हैं

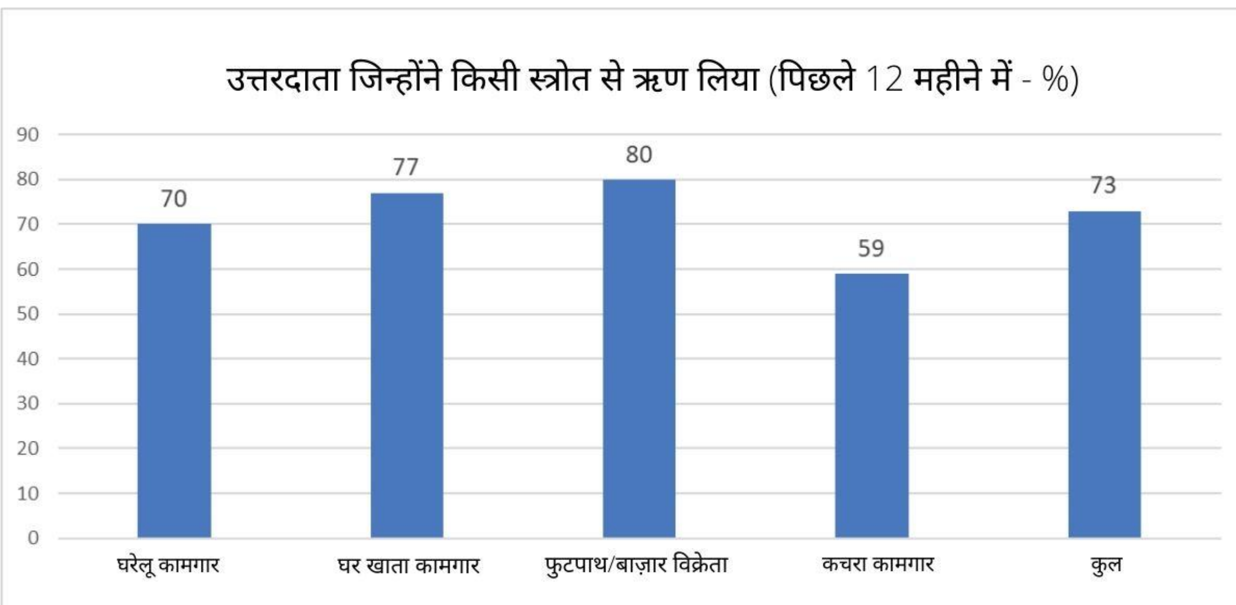

रिकवरी और उसके परे: असंगठित कामगारों की जरूरतें और मांगें

जैसा कि पहले उल्लेख किया गया, असंगठित कामगारों को कोविड संकट के विभिन्न प्रभावों से निपटने के लिए सरकार से बहुत कम सहयोग मिला. एक पुरुष कचरा कामगार ने मार्मिक ढंग से कहा, "मैं सरकार से क्या मांगूंगा? वे क्या कर रहे हैं? अगर सरकार वास्तव में चाहती है, तो हमारी मदद कर सकती है. लेकिन वे ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि इच्छाशक्ति नहीं है".

सर्वेक्षण के तहत शामिल किए गए चारों कार्यक्षेत्र रोजगार के बहुत महत्वपूर्ण स्रोत हैं और इनमें कई तरह के आवश्यक कार्य सम्मिलित हैं, इसके बावजूद इनके योगदान को बहुत कम पहचान मिली है, जिसके फलस्वरूप इनके सहयोग के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं है. भविष्य में रिकवरी करने हेतु कामगारों ने बताया की आजीविका को फिर से शुरू करने में सहयोग उनकी सबसे महत्वपूर्ण जरूरत है, क्योंकि नियमित रूप से कमाने की उनकी क्षमता ही उन सभी दूसरी समस्याओं का रामबाण समाधान होगी जिनका वे सामना कर रहे हैं. यहां तक कि मध्य-2021 में, सर्वेक्षण में शामिल बड़ी संख्या में कामगारों ने तत्काल सहयोग की जरूरत बताई. कामगारों ने बताया कि इस सहयोग में लंबे समय तक भोजन आपूर्ति के सार्वजनिक प्रावधान किए जाने चाहिए. साथ ही बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए नकद राहत दी जाने की आवश्यकता है. स्वास्थ्य, आजीविका और घरेलू देखभाल के तिहरे संकट की शुरुआत के बाद से, असंगठित कामगारों, उनके संगठनों और सहयोगियों ने लगातार निम्नलिखित प्रमुख मांगें उठाई हैं. इस समय इन सिफारिशों को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ने की तत्काल आवश्यकता है.

मान्यता और विनियमन:

- घरों और असंगठित कार्यस्थलों पर काम करने वालों सहित सभी असंगठित कामगारों को राष्ट्रीय श्रम कानूनों और विनियमों के दायरे में लाया जाए, जो सही काम और वेतन का अधिकार सुनिश्चित करते हैं.

- सभी असंगठित कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा तक पहुंच बढ़ाने की जरुरत है, विशेष रूप से बच्चों की देखभाल और स्वास्थ्य बीमा की उपलब्धता और सुविधा प्रदान करना- जागरूकता बढ़ाने और पंजीकरण में तेज़ी लाना, और पहुंच को आसान बनाना. योजनाओं की सुवाह्यता में कमी के कारण मौजूदा योजनाओं का लाभ नहीं उठा पा रहे प्रवासी कामगारों के लिए योजनाओं तक पहुंच को आसान बनाने पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए.
- अगस्त 2021 में शुरू हुई ई-श्रम पंजीकरण प्रक्रिया एक प्रशंसनीय पहला कदम है, लेकिन आवश्यक पंजीकरण और दस्तावेजीकरण की गति को लेकर कई समस्याएं हैं. केंद्र और राज्य सरकारों को इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन में अधिक सक्रिय भूमिका निभानी होगी और नकद सहायता, सामाजिक सुरक्षा लाभ और अन्य योजनाओं को भी इसमें जोड़ना होगा, जिनका कामगार तुरंत लाभ उठा सकें.

> “ हम चाहते हैं कि हमारे कार्यक्षेत्र को पुनर्जीवित करने के लिए हमारे पेशे को मान्यता दी जाए. "- पुरुष फुटपाथ विक्रेता
>
> “ हम सिर्फ स्थायी काम और पर्याप्त वेतन चाहते हैं. साथ ही अगर हमें थोड़े लंबे समय के लिए राशन उपलब्ध कराया जा सके, तो इससे भी मदद मिलेगी.” - महिला घरेलू कामगार
>
> “ हम चाहते हैं कि हमारा राशन कार्ड और आधार कार्ड तैयार हो सके. इस वजह से हमें अभी भी राशन नहीं मिल पा रहा है."- महिला घर खाता कामगार

आजीविका के अवसर सक्षम करें:

- सुनिश्चित करें कि आय सुरक्षा में आजीविका की सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा दोनों शामिल हों. असंगठित कामगार, जिन्हें बड़े पैमाने पर आजीविका के नुकसान का सामना करना पड़ा है, उनको कोविड-19 के समय में आय की सुरक्षा से वंचित नहीं किया जा सकता है.
- न्यूनतम रोजगार गारंटी और बुनियादी न्यूनतम मजदूरी प्रावधानों के माध्यम से नौकरियों का सृजन करने लिए रोजगार-परक आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय सरकारी उपाय लागू किए जाएं.
- आजीविका को फिर से शुरू करने के लिए असंगठित कामगारों का समर्थन करें:
  - कचरे की छंटाई और अलगाव के लिए विकेंद्रित जगहें निर्धारित कर और निजी कंपनियों द्वारा कब्जा रोक कर कचरा कामगारों की कचरे तक पहुंच सुनिश्चित की जानी चाहिए.
  - फुटपाथ विक्रेताओं को अपनी आजीविका फिर से शुरू करने के लिए पूंजी की आवश्यकता है, और यह पूंजी नकद सहायता के रूप में होनी चाहिए, न कि कर्ज के रूप में, जिससे वे और अधिक कर्ज में दब जाते हैं.

    फुटपाथ विक्रेताओं को उनकी जगह से बेदखल होने, अधिकारियों द्वारा उत्पीड़न और फुटपाथ बिक्री की जगह को बंद होने से भी बचाना होगा. बीमारी फैलने से रोकने के सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों को पूरी तरह से कामगारों पर नहीं डाला जाना चाहिए, बल्कि स्थानीय सरकारों को विक्रेताओं के साथ भागीदारी करनी चाहिए ताकि सभी के लिए सामाजिक दूरी और सुरक्षित बाजार तक पहुंच सुनिश्चित हो सके.
  - घर खाता कामगारों के प्रति उसके नियोक्ता की जिम्मेदारी सुनिश्चित करें. इन उत्तरदायित्वों में न्यूनतम मजदूरी की गारंटी, मनमाने ढंग से नौकरी देने और निकालने से रोकने के लिए प्रोटोकॉल, एवं सुरक्षात्मक तथा स्वास्थ्य सहायता प्रदान करना शामिल हैं.
  - घर से काम करने वालों के लिए आपूर्ति श्रृंखला में राहत और राष्ट्रीय मानकों के अनुसार तय वेतन की दरों पर उनके काम की आपूर्ति को बहाल किया जाए.

“हम कुछ काम चाहते हैं और सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारा वेतन समय पर दिया जाए. मैं सिलाई का अपना काम भी शुरू करना चाहती हूँ.” - महिला घरेलू कामगार

“हम सरकार की जिम्मेदारी हैं. कीमतों में इतनी वृद्धि हुई है और हमारी कमाई घटकर शून्य हो गई है. हमें अपने श्रम से पर्याप्त धन नहीं मिल पा रहा है. सरकार को हमारी कमाई बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए. साथ ही, जब तक स्थितियां बेहतर न हो जाएँ उन्हें भोजन राशन की व्यवस्था करनी चाहिए. ” - पुरुष कचरा कामगार

“कंपनियों को कचरे का प्रबंधन करने में कोई विशेषज्ञता या जानकारी नहीं है, वे कूड़ा बीनने वालों को उसी काम के लिए कम वेतन देते हैं जो वे पहले से करते आ रहे हैं. ऐसे में कंपनियों को इस काम में क्यों लाया जाना चाहिए? अगर सरकार हमें कुछ दिशा निर्देश देती है तो हमें मंज़ूर है और हमें उनका पालन करने में खुशी होगी. हालांकि, कचरा कामगार समुदाय को पूरी तरह से नजरअंदाज करके सरकार को एकतरफा निर्णय लेने से पहले हमसे बात करनी चाहिए. ”- पुरुष कचरा कामगार

“मुझे पीएम स्वनिधि ऋण मिला, लेकिन इससे कोई मदद नहीं हुई क्योंकि यह बहुत छोटी राशि थी. मुझे इसे दैनिक खर्चों के लिए इस्तेमाल करना पड़ता था, और काम इतना भी नहीं है कि कर्ज चुका सकें. ”- पुरुष फुटपाथ विक्रेता

"हमें उचित मजदूरी और पर्याप्त छुट्टियाँ मिलनी चाहिए. अगर हम बीमार हो जाएँ तो हमारा एक भी रूपया नहीं कटना चाहिए. यह सरकार से हमारी मांग है ”- महिला घरेलू कामगार

"हम सिर्फ नियमित काम चाहते हैं, हमें सह-ठेकेदारों से नियमित रूप से काम नहीं मिलता ... कभी-कभी काम मिलता है, कभी-कभी हम बैठे रहते हैं ... और हमें काम के अनुपात में एक निश्चित दर की आवश्यकता है...बड़े और छोटे काम के लिए समान दर नहीं होनी चाहिए... अब कोविड के बाद, वे बहुत कम दर पर सब काम करवाने की उम्मीद कर रहे हैं. ” - महिला घर खाता कामगार

स्वास्थ्य जोखिम को कम करें:

- घरों और असंगठित कार्यस्थलों, दोनों स्थानों पर पानी और स्वच्छता सुविधाओं तक पहुंच सुनिश्चित करें, साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर इनकी पहुंच बढ़ाएँ.
- असंगठित कामगार, जो आवश्यक सेवाएं दे रहे हैं और अपने काम के माध्यम से सार्वजनिक स्वास्थ्य में योगदान दे रहे हैं, उनके लिए पीपीई किट और सैनिटाइज़र का प्रावधान तय करें. इनमें आने वाले खर्च का बोझ कामगारों पर नहीं पड़ना चाहिए.
- असंगठित कामगारों के लिए स्वास्थ्य और बीमा योजनाओं को सुनिश्चित करना.
- गुणवत्तापूर्ण सामुदायिक परीक्षण और क्वारेंटाइन सेंटरों तक पहुंच प्रदान की जाए जो कि सस्ते और निकट हों.

नुकसान न करें:

- जैसा कि स्ट्रीट वेंडर एक्ट, 2014 में निहित है, सुनिश्चित करें कि फुटपाथ विक्रेताओं को बेदखल न किया जाए.
- पुलिस और नगर निगम के अधिकारियों द्वारा कचरा कामगारों और फुटपाथ विक्रेताओं का उत्पीड़न बंद हो.

- रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (RWA) द्वारा अन्यायपूर्ण नियमों और विनियमन को रोकें जो घरेलू कामगारों के काम करने के अधिकार को सीमित करते हैं.

हमारे लिए, हमारे बिना कुछ भी नहीं:

- असंगठित कामगारों और उनके संगठनों को उन सभी निर्णयों में प्रमुख हितधारकों के रूप में शामिल करें जो उनके काम पर प्रभाव डालते हैं.
- अंतिम व्यक्ति तक सरकारी राहत और पुनरुद्धार कार्यक्रमों की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए एमबीओ और नागरिक समाज को शामिल करें.

समावेशी शहर नियोजन और नीतियों के माध्यम से असंगठित कामगारों के लिए रहने और काम करने की अच्छी स्थिति सुनिश्चित करना:

- कार्यस्थलों तक सुरक्षित पहुंच सुनिश्चित करके (जिनमें सार्वजनिक स्थानों पर बुनियादी सुविधाएं दिए जाना शामिल है), एवं श्रम-आधारित गहन विकास को बढ़ावा देकर शहर में असंगठित आजीविका को पहचान और सहयोग दिया जाए.
- कचरे से सम्बंधित कार्य के लिए विकेन्द्रीकृत स्तरों पर औपचारिक स्थान आवंटन, बिक्री के स्थानों की मान्यता, सामुदायिक कार्य केंद्र आदि.
- शहर में असंगठित कामगारों के लिए उचित आवास और किराए की मोहलत प्रदान करें.
- सुरक्षित और गुणवत्ता वाले सार्वजनिक परिवहन तक पहुंच सुनिश्चित करें.

"हम घर के किराया भरने के लिए मोहलत चाहते हैं और किसी प्रकार की नकद सहायता भी चाहते हैं. "- महिला घरेलू कामगार

"सरकार को हमें बिना किसी उत्पीड़न और धमकी के अपना काम करने की अनुमति देनी चाहिए. मैं उनसे कम से कम इतनी उम्मीद करता हूं. अगर मैं काम कर सकूं, तो मैं कम से कम इतना कमा सकता हूं कि अपने परिवार का भरण पोषण कर सकूं." - पुरुष कचरा कामगार

कोविड-**19** संकट और असंगठित अर्थव्यवस्था, ग्लोबल नेटवर्क वूमन इन इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट : ग्लोबलाइजिंग एंड आर्गेनाइजिंग (WIEGO) और स्थानीय भागीदार संगठनों के बीच एक सहभागिता है, जो कनाडा के इंटरनेशनल डेवलपमेंट एंड रिसर्च सेंटर (IDRC/CRDI) के सहयोग से निम्न 12 शहरों में असंगठित कामगारों का प्रतिनिधित्व करते हैं: अकरा (घाना); अहमदाबाद (भारत); बैंकॉक (थाईलैंड); डकार (सेनेगल); दार एस सलाम (तंजानिया); दिल्ली (भारत); डर्बन (दक्षिण अफ्रीका); लीमा (पेरू); मेक्सिको सिटी (मेक्सिको); न्यूयॉर्क शहर (यूएसए); प्लेवेन (बुल्गारिया); और तिरुप्पुर (भारत) मिश्रित-विधियों वाली इस लॉगिट्यूडनल स्टडी में असंगठित कामगारों के सर्वेक्षण के लिए प्रश्नावली और असंगठित कार्यकर्ताओं के नेताओं एवं अन्य प्रमुख सूचना प्रदाताओं के साथ अर्द्ध संरचित साक्षात्कार सम्मिलित है, जो सभी फोन पर किए गए हैं . ज्यादा जानकारी के लिए देखें-
wiego.org/COVID-19-Global-Impact-Study.

असंगठित रोजगार में महिलाएं: ग्लोबल नेटवर्क वूमन इन इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट : ग्लोबलाइजिंग एंड आर्गेनाइजिंग **(WIEGO)** एक वैश्विक नेटवर्क है जो असंगठित अर्थव्यवस्था में काम करने वाले गरीबों, विशेष रूप से महिलाओं की आजीविका सुनिश्चित करने के लिए

उनको सशक्त बनाने पर केन्द्रित है. हमारा मानना है कि सभी कामगारों को समान आर्थिक अवसर, अधिकार, सुरक्षा और हक मिलना चाहिए. WIEGO असंगठित अर्थव्यवस्था पर आंकड़ों में सुधार और ज्ञान का विस्तार करके, असंगठित कार्यकर्ता संगठनों के बीच नेटवर्क और क्षमता का निर्माण करके और स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नीतियों को प्रभावित करने वाले नेटवर्क और संगठनों के साथ संयुक्त रूप से परिवर्तन को बढ़ावा देता है.अधिक जानकारी के लिए www.wiego.org पर जाएं.

यह कार्य इंटरनेशनल डेवलपमेंट एंड रिसर्च सेंटर, ओटावा, कनाडा से अनुदान की सहायता से पूरा किया गया था. यहां व्यक्त किए गए विचार आवश्यक रूप से आईडीआरसी या उसके बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं.

IDRC · CRDI

International Development Research Centre
Centre de recherches pour le développement international

Canada